



तापमान 26 - 15
आर्द्रता 60%
सूर्योदय: 6:20 सूर्यास्त: 17:14



समाज

कोलकाता, माघ कृष्णपक्ष तृतीया, वि.स. 2081, पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये **मुख्यालय:** नियत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं।

स्थानीय खबरें पृष्ठ तीन, चार और पांच पर

सैन्य सामर्थ्य अधिक सक्षम बनाना भारत की

प्राथमिकता, मकसद विरतारवाद नहीं विकासवाद: मोदी



मुंबई: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार का कहा कि 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य अधिक सक्षम और आधुनिक होना उसकी प्राथमिकताओं में से एक है लेकिन इसका मकसद विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की भावना है। मुंबई स्थित नौसेना डॉक्याड में नौसेना के अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूत्र, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत पूरे विश्व और खासकर 'स्लोबल साउथ' में एक

भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है।

बैंक लॉकर घोटाला: अभियुक्तों के बयान के आधार पर लगभग 11 करोड़ के आभूषण जब्त

कोलकाता: इंडियन बैंक पार्क स्ट्रीट ब्रांच में बैंक लॉकर घोटाला से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में बैंक के लॉकर इंवर्जर मिथुन सी और मौमिता सी के गिरफ्तार किया था दोनों आरोपियों को 10 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया, जो 22 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा।

पूछताला में हुआ बड़ा खुलासा

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूछताला के द्वारा दोनों आरोपियों ने अपनी सलिलता स्वीकार की है। मुख्य आरोपी मौमिता सी के बयान के आधार पर पुलिस ने बीती रात कब्जा थाना क्षेत्र में तस्करी के एक फ्लैट (87/41) पर छापा मारा। छापेमारी के द्वारा पुलिस को भारी मात्रा में चोरी का

लगभग 11 करोड़ के आभूषण जब्त

किए हैं।

1. 27 दायरमंड आभूषण: विभिन्न

रूपये में तेजी जारी, 13 पैसे बढ़कर

86.40 प्रति डॉलर पर

मुंबई: स्थानीय शेयर बाजारों से अनुकूल संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में नपी के बीच अंतर्वेदी विदेशी मुद्रा विनियम बाजार में रुपये में लगातार दूसरे सत्र में मजबूती जारी होती और यह 13 ऐसे की बढ़त के साथ 86.40 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बढ़ हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रा सूचकांक भी रिकॉर्ड ऊँचाई से नीचे आया, जिससे स्थानीय मुद्रा में तेजी आई हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार निकासी से वरावार कायम रहा।

बीएसएफ ने 13 बांग्लादेशी धूसपैठियों को खदेड़ा, तीन मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया

कोलकाता: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर उत्तर 24 परगाना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालाबाड़ी में तस्करी और धूसपैठ के कई प्रयासों को गिरफ्तार कर दिया है। 13 बांग्लादेशी धूसपैठियों को वायाप खेड़े दिया और तीन मवेशी तस्करों को गिरफ्तार कर दिया। इसके अलावा, बीएसएफ जवानों ने इन अधियायों के द्वारा ग्रन्ति विभिन्न तात्पुरता के अनुसार, बांग्लादेशी धूसपैठियों को वायाप खेड़े दिया और तीन मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया। बीएसएफ के एक बयान के अनुसार, 14 जनवरी को उत्तर 24 परगाना में चास्तरामारी की जान खेले गए एक बीएसएफ जवानों ने एक स्टैंड ग्रेनेड फेंका, लेकिन तस्करों से धारदार हथियारों से हमारे द्वारा खेले गए एक अलग अधियाय में नूरांग जीसी चौकी की आड़ में भाग गए। नादिया जिले में एक अलग अधियाय में, नूरांग जीसी चौकी से हो गए। नादिया जिले में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर तीन बांग्लादेशी धूसपैठियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से तीन गांव बरामद किया।

अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सकारात्मक और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय

ने बुधवार का कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र कर्मसूल और संघीय सर्वोपराधिकारियों के साथ जुटाए गए।

नवी दिल

